DR. BAPU KALDATE: I am sorry for that. वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो बड़ा सफेद हाथी बन गया है ।

It may be because of the burden of the colleges.

मैं यह नहीं मानता कि सभी लोग वैसे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो बोझ आ रहा है । इसका नतीजा यह होता है कि यहीं छोटे-छोटे कालेजों की तरफ देखते तक नहीं है मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की चार शिकायतें थीं उन्होंने पैसा मंजूर किया था, उसके लिए मैं महीनों लिखता रहा । लेकिन हमने देखा कि जब हम फोन करते हैं, तो एक अफसर कुर्सी में नहीं होते या मीटिंग में होते हैं, हमसे नहीं मिलते, हमको चेयरमैन तो मिल पाये, लेकिन अफसरान नहीं मिल पाए अभी तक । दो-दो साल हो गए हमारे कम्प्यूटर को मंजूर हुए । आप खुद देखिए अब दो साल हो गए, कितनी कीमत बढ़ गयी । इसको आप कुछ दुरुस्त कीजिए । इसका डीसेंट्रलाइजेशन कीजिए और कोर्डिनेशन की व्यवस्था कीजिए । मैं मानता हूं कि--

without co-ordination, there will be total degeneration.

तो मैं डीजनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं । मैं यह भी मानता हूं कि इंटर डिसपिलनरी कोर्सेस की बात सोचिए, जो आजकल चल रही है । दसवीं तक जाता है लड़का तो उसका भाग्य सील हो गया और बारहवीं में आकर तो पूरा सील हो गया, चाहे साइंस हो, चाहे मेडीकल हो या वह हो, वह हो--

There is a thinking, and also there is a practice of inter-disciplinary courses. Suppose I go in for commerce and I want to change for medical education Ti can change it

मैं कहता हूं इस बारे में बहुत सुझाव दे सकता हूं, मैं आपसे बात करके भी दे सकूंगा । आपने मुझे ज्यादा समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । धन्यवाद ।

I. STATEMENT BY MINISTER

Re. Government's paper on Long Term Fiscal Policy

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH). Sir, In my Budget Speech earlier this year I had indicated that the Government will be moving towards the formulation of a Long Term Fiscal Policy co-terminous with the Plan. The Seventh Plan was placed in the House a few days ago. It is my privilege to place the Government's Paper on Long Term Fiscal Policy before the House today.

The basic purpose of thi$_s$ document is to impart a perspective to our annual exercises of Budget making. The Government'g views on this matter are now before you. j look forward to a full and vigorous debate on this subject in Parliament and in the country.

As the Hon'ble Members would no doubt wish to study the document themselves, I will not take their valuable time by going over its contents. However, I would like to take this opportunity to thank the Hon'ble Members for the trouble they have taken in giving us the benefit of their views in discussions in the meetings of Consultative Committee and other fora on this subject. I may add that I have benefited greatly from the discussions that I have had with economists, labour leaders, industrialists and representatives of agriculturists on this subject.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): A$_s$ we would have another opportunity to discuss this matter. I would request hon. Members seeking clarifications to be very brief. Shri Jagesh Desai.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Sir, the document is not with us. I would like the hon. Minister to give us s°nie broad outlines of tbis policy. Nothing is there in the statement.

SHRl MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): At least the outlines should havo been given.

SHRI JAGESH DESAI: I do not know what is the policy.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am entirely in your hands.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Well, we can do without the clarifications now. We can take it up later. Now we will continue with the discussion on the Education Policy.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): We have decided, as ray hon. friend knows, in the Business Advisory Committee that there will be a debate on this, not in this session but in the next session.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): So now we continue with the discussion on the Education Policy. Before I call the next speaker, I request hon. Members again to be particular about time. Shri Sudhakar Pandey.

GOVERNMENT MOTION ON "CHALLENGE OF EDUCATION— A POLICY -PERSPECTIVE".. .contd.

श्री सुधाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, शिक्षा में चुनौती विषयक परिचर्चा-पत्र सारे देश में विचार-मंथन का विषय बना हुआ है और सौभाग्य है कि इस समय जो शिक्षामंत्री है, उन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम अंश शिक्षा के लिए लगाया है और आज भी शिक्षा में उनकी रुचि है । शिक्षा के लिये मानव-संसाधन विभाग की स्थापना की गयी है और उसके माध्यम से यह यत्न किया जा रहा है कि शिक्षा पुन : कालजयी बने और इसके माध्यम से जीवन का भविष्य रचा जाए । साथ ही जो अन्तराल बढ़ता जा रहा है, जीवन में और विज्ञान में, उसको जोड़ा जाय । इस पत्र में यह सारी बातें संकेत रूप में आ गयी हैं । इस पत्र में शिक्षा के संबंध में वे सारी बातें संकेत रूप में आ गई हैं जो आनी चाहिए । और बहुत सी चीजें नहीं हैं । शिक्षा की स्थिति वही है जैसे तुलसीदास ने कहा है — "हरिअनन्त हरि कथा अनन्ता," उसका अन्त नहीं है ।

शिक्षा के बारे में अब हम कोई बात करें तो सबसे पहले हमें साधन की बात करनी चाहिए । इसके पहले भी बहुत से आयोग बने थे और उन आयोगों के माध्यम से बहुत से अच्छे-अच्छे सुझाव दिए गए थे, किन्तु उन सुझावों का अंश-अंश हमने लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि उस बात की उपलब्धि नहीं हुई जिसकी उपलब्धि के लिए हम प्रयत्नशील थे । शिक्षा पर और खर्चा हो या न हो, किन्तु जितना खर्चा हो या जितने साधन जुटाने हैं उनकी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए और उसी के माध्यम से आगे बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए ।

शिक्षा की जब हम बात करते हैं और संसाधन मंत्रालय की बात करते हैं तो पहली बात यह सोचनी चाहिए कि हमारे भीतर कितना समन्वय है । शिक्षा को खंड-खंड देखने के हम आदी हो गए हैं, प्राइमरी शिक्षा को अलग देखते हैं, हाई स्कूल की शिक्षा को अलग देखते हैं, विश्वविद्यालय की शिक्षा को अलग देखते हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि इन तीनों में सामंजस्य नहीं हो रहा है । इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि हमारे मंत्रालय में जितनी शिक्षा से सम्बन्धित चीजें हैं उनमें भी समन्वय नहीं हुआ है । अगर इधर ऐसा हुआ हो तो मैं नहीं जानता । मेरा ऐसा अनुभव है कि यू जी सी का कोई समन्वय एन सी ई आर टी से नहीं है, इतिहास परिषद का समन्वय दर्शन परिषद से नहीं है । इतना ही नहीं इस क्षेत्र में एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से किसी प्रकार का समन्वय नहीं है । अभी हमारे मित्र